सत्यमेव जयते

षोडश

बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 07 अग्रहायण, 1941 (श०) / 28 नवम्बर, 2019 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 06

(1)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	..	..	..	01
(2)	नगर विकास एवं आवास विभाग	..	..	..	03
(3)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	..	..	..	01
(4)	कृषि विभाग	..	..	..	01
				कुल योग --	06

कार्रवाई करना

11. श्री अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में खाद्य सामग्री सहित सभी जिन्सों, मसालों, सब्जियों एवं फलों के मूल्य में सरकार का नियंत्रण नहीं होने से खुदरा मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है (टमाटर 60-80 रुपये, प्याज 80-100 रुपये प्रति किलो) जिससे आम आदमी के क्रय से बाहर हो गये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि मूल्य बढ़ोतरी का मूल कारण जमाखोरी है, जिसपर राज्य सरकार अंकुश लगाने में विफल हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार संलिप्त पदाधिकारियों पर समुचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

12. श्री भोला यादव--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम में पूर्व से मछली व्यापारियों, दुग्ध व्यवसायियों, फल विक्रेताओं के लिये स्थल चिह्नित कर व्यवसाय करने हेतु स्थल आवंटित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त व्यवसायियों द्वारा समय-समय पर नगर निगम एवं अन्य प्राधिकारों द्वारा निर्धारित टैक्स का भी भुगतान किया गया है, जबकि बिना पूर्व नोटिस एवं अतिक्रमण स्थल चिह्नित किये ही जिला प्रशासन द्वारा दुकानों को आनन-फानन में हटाये जाने से गरीब व्यवसायी आहत एवं परेशान है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

कार्रवाई करना एवं होल्डिंग टैक्स माफ करना

13. श्री अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम की अकर्मण्यता के कारण माह सितम्बर, 2019 में पूरा पटना जलमग्न हो गया था, जिसमें लाखों के धन-जन की हानि हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम द्वारा ससमय छोटे-बड़े नालों की सफाई नहीं की गई तथा सम्प हाऊस के बन्द रहने के कारण जल-जमाव हुआ था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पटना नगर क्षेत्र में हुई धन-जन की हानि के लिये उत्तरदायी पदाधिकारियों को चिह्नित कर कार्रवाई करते हुये एक वर्ष के लिये निवासियों के होल्डिंग टैक्स माफी करने का विचार रखती नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

14. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकार ने वर्ष 2018 में ही राज्य के सभी पंचायतों में पंचायत कृषि कार्यालय खोलकर कृषकों की सुविधा हेतु किसानों को सरकार के कृषि योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त हो इसका निर्णय लिया था, यदि हाँ, तो सरकार के निर्णय के एक वर्ष से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी राज्य के किसी पंचायत में कृषि कार्यालय चालू नहीं किये जाने का क्या औचित्य है ?

प्रोसेसिंग मशीन लगाना

15. श्री समीर कुमार महासेठ--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वायु एवं जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक कचरा है, फिर भी राज्य के किसी भी नगर निकाय क्षेत्र में कचरा प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगे रहने के कारण आम नागरिक कचरे को जलाकर निष्पादित कर देते हैं, जिससे पर्यावरण बुरी तरह से प्रभावित होता है, यदि हाँ, तो सरकार वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने हेतु राज्य के सभी नगर निकायों में कचरा प्रोसेसिंग मशीन कबतक स्थापित कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

16. श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 को प्रकाशित शीर्षक ''राज्य में जमीन की 3.57 करोड़ जमाबंदी में से 1.13 करोड़ का लगान डाटा ही अधूरा'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में जमीन की कुल जमाबंदी की संख्या 3 करोड़ 57 लाख है, जिसमें से मात्र 2 करोड़ 44 लाख जमाबंदी का ही अभिलेख सरकार के पास उपलब्ध है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 3 करोड़ 57 लाख जमाबंदी में से 1 करोड़ 13 लाख जमाबंदी का डाटा उपलब्ध नहीं रहने के कारण सरकार को राजस्व की भारी क्षति हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो अभीतक 1 करोड़ 13 लाख जमाबंदियों का अभिलेख अद्यतन नहीं करने का क्या औचित्य है ?

पटना : बटेश्वर नाथ पाण्डेय,

दिनांक 28 नवम्बर, 2019 (ई0) । सचिव,

बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 107(एल0ए0), 2019-20-डी0टी0पी0-550